मित्र-राष्ट्रों के बीच चयन कैसे नहीं करें

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- सुहासिनी हैदर (संपादक)

3 नवम्बर, 2018

''अमेरिका से प्रतिबंध में मिली छूट भारत के लिए एक खोखली जीत साबित हो सकती है।''

मई 2012 में, अमेरिकी विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन ने ईरान से अपने तेल आयात में कटौती करने के लिए भारत को मनाने के लिए ईरान के साथ संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) या परमाणु समझौते पर बातचीत करने वाले पश्चिमी देशों की ओर से दिल्ली का दौरा किया था। अपनी पुस्तक हार्ड चॉइसेस (Hard Choices) में, उन्होंने भारत सरकार के साथ अपनी कठिन लड़ाई का जिक्र किया है, जिसका कारण उन्होंने यह बताया कि भारत को छह पक्षीय वार्ता के लिए बैठक में लौटने के लिए ईरान पर दबाव डालने में मदद करने की जरूरत थी। आखिरकार, भारत अपने आयात में केवल 15% कटौती करने पर सहमत हो गया। लेकिन संचयी वैश्विक दबाव के कारण ईरान पर वांछित प्रभाव पड़ा, जहां मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई थी और तेल निर्यात हर दिन 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लगभग 1 मिलियन हो गया था। अंततः जेसीपीओए वार्ता के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता किया, जिसने वार्ता को चौथाई कर दिया था।

बदलता समय

चूंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में नई दिल्ली में कई प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है और इन सभी के पास एक ही मिशन है, लेकिन एक पूरी तरह से अलग पृष्ठभूमि के साथ। ध्यान देने वाली बात है कि जो रियायत अमेरिका ने भारत को प्रदान की है वो भारत से कोई रिश्ता कायम रखने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन जेसीपीओए से पहले ही बाहर हो चुका है। इस सौदे में शामिल किसी भी अन्य देश ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने इस निर्णय के बाद अमेरिका के संबंध में नाराजगी व्यक्त की है। इसके अलावा, अमेरिका ने इसका कोई सबूत नहीं दिया है कि ईरान ने किसी भी तरह से जेसीपीओए की शर्तों का उल्लंघन किया है, वास्तव में तो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जून रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार, ईरान के यूरेनियम और हैवी वाटर के भंडार के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के समझौते के साथ अनुपालन में था।

2012 के विपरीत, अमेरिका के ईयू सहयोगी अब विशेष भुगतान तंत्र रखने के लिए रूस और चीन जैसे कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से तेहरान को व्यापार का समर्थन करने के उद्देश्य से, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरानी शासन परमाणु समझौता से बाहर ना हो।

भारत के लिए, छूट के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंध योजना का असर कई गुना होगा। शुरुआत में इसके परिणाम देखे तो हम पाएंगे की यह किसी सदमे से कम नहीं है क्योंकि यह देखते हुए कि ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है यह प्रतिबंध तेल आयात बिल से निपटेगा। दूसरा प्रभाव चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश पर होगा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिबंध दोनों का सामना करेगा: क्योंकि शिपर्स, बंदरगाह आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारिक कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने से इंकार कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत ने कुछ साल पहले चाबहार में भारी समान उठाने वाले क्रेनों के लिए निविदाएं खोली थीं, इसे कोई लेने वाला नहीं मिला और अंततः 2017 में जेडपीएमसी को अनुबंध देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंदरगाह में भारत के 500 मिलियन डॉलर के निवेश और पाकिस्तान को रोकने और अफगानिस्तान और मध्य एशियाई व्यापार लाइनों तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के लिए 2 अरब डॉलर की योजना भी इससे प्रभावित होगी। आखिरकार, भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर असर पड़ेगा, जो ईरानी-अरब विभाजन को गहरा कर सकता है, इसके अलावा, अफगानिस्तान के विकल्पों में कमी आई है और नाराज ईरान चीन-रूस के करीब आते प्रतीत हो रहा है।

भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उपर्युक्त सभी परिणाम इस बात पर ध्यान दिए बिना होंगे कि क्या अमेरिका भारत को प्रतिबंधों के लिए छूट देता है या नहीं। छूट सूची, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जारी किया है, सोमवार को जारी किया जाएगा। यू.एस. ने कहा है कि वह केवल अस्थायी छूट जारी कर रहा है और छूटकर्ता इस शर्त से सख्ती से जुड़े हुए हैं कि वे ईरान से अपनी आयत में कटौती करेंगे।

ईरान के लिए विकल्प

इस बीच, अगर भारत अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करता रहता है तो ईरान की प्रतिक्रिया पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। व्यापार के स्तर घटने के साथ, ईरानी शासन का चाबहार विकल्प में रुचि कम हो सकता है और वह अपने मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भारत की विशाल योजनाओं को दूर करता है। चिंता यह भी है कि भारत के सभी बलिदान शून्य हो सकते हैं, क्योंकि श्री ट्रम्प ईरान पर अपने फायदे के लिए दबाव का उपयोग कर सकते हैं और बाद में तेहरान के साथ संभवत: वार्तालाप कर सकते हैं। यू.एस. द्वारा भारत को प्योंगयांग में अपना मिशन बंद करने की बात कहे जाने के कुछ महीनों बाद, श्री ट्रम्प उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग-अन के साथ सिंगापुर में एक शिखर सम्मेलन की योजना बना रहे थे।

भारी लागत और किसी भी लाभ की पूरी अनुपस्थिति में, यह आश्चर्य की बात है कि अमेरिकी सरकार के कार्यों के विरोध में मोदी सरकार अधिक मुखर नहीं रही है। इस साल मई में, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जोर देकर कहा था कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को मानता है, एकतरफा प्रतिबंधो का पालन नहीं करता है। इस बीच, भारतीय अधिकारियों ने वाशिंगटन के लिए ईरान और सीएएटीएसए प्रतिबंधों से भारत के छूट का हकदार होने के कारणों पर चर्चा करने के लिए एक आधार रेखा बनाई है। इन अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका को ईरान से तेल की खरीद में भारत की ऊर्जा आवश्यकता और 35-50% की कटौती के बारे में जानकारी दी गई है। सीएएटीएसए के मोर्चे पर, यू.एस. को रूस पर भारतीय रक्षा निर्भरता में उल्लेखनीय कमी का आश्वासन दिया गया है और हाल ही में खरीदी गई एस -400 मिसाइल प्रणाली की तरह कोई भी हथियार खरीदा नहीं गया है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी हितों के खिलाफ किया जाएगा।

नतीजतन, यदि अमेरिका प्रतिबंधों के साथ कायम रहता है, तो यह भारतीय कूटनीति की एक महत्वपूर्ण विफलता होगी और अगर छूट का संकेत मिलता है, जैसा कि संकेत दिया गया है, तो यह एक खोखली जीत होगी।

GS World टीम...

भारत-अमेरिका संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों के बावजूद उस देश से तेल खरीदने पर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाने की घोषणा की है।
- अमेरिका के इस कदम को उन देशों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जो ईरान से तेल खरीदने को इच्छुक थे।
- भारत, ईरान से कच्चे तेल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत अब ईरान से कच्चे तेल की खरीद को सालाना डेढ़ करोड़ टन तक सीमित रखना चाहता है।
- इससे पहले 2017-18 में भारत की ईरान से तेल खरीद दो करोड़ 26 लाख टन यानी चार लाख 52 हजार बैरल प्रतिदिन के स्तर पर रही।
- भारत, जापान और दक्षिण कोरिया सहित आठ देशों को ईरान से तेल आयात करने पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। अन्य देशों के नाम सोमवार को जारी किए जाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

- जुलाई, 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच परणाणु समझौता हुआ था।
- अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने समझौते के तहत ईरान को परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले में बैन से राहत दी थी। लेकिन मई, 2018 में ईरान पर ज्यादा दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता तोड़ दिया।
- ट्रंप ने ईरान में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों को निवेश बंद करने के लिए कहा था। अमेरिका ने भारी जुर्माने की भी धमकी दी थी और ईरान से कच्चे तेल को खरीदने वाले देशों को 4 नवंबर तक आयात बंद करने को कहा था।

भारत-ईरान

- भारत-ईरान से कच्चे तेल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।
- भारत अब ईरान से कच्चे तेल की खरीद को सालाना डेढ करोड़ टन तक सीमित रखना चाह रहा है।
- इससे पहले 2017- 18 में भारत की ईरान से तेल खरीद दो करोड़ 26 लाख टन यानी चार लाख 52 हजार बैरल प्रतिदिन के स्तर पर रही।

GS World Committed To Excellence

भारत के लिए अहम क्यों?

- नई दिल्ली ने अपनी अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव के कारण ईरान से तेल आयात जारी रखने पर दबाव डाला था।
- सितंबर में भारत-यूएस 2 + 2 वार्ता के दौरान, अमरीका ने भारतीय पक्ष से कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना खुद वाशिंगटन के हित में नहीं है।
- उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और माइक पोम्पियो ने ईरान से तेल आयात जारी रखने के मुद्दे पर चर्चा की थी।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत के कच्चे तेल की कुल जरूरतों का 85 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का 34 प्रतिशत आयात से पूरा किया जा रहा है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) पर वार्ता हुई थी?

(a) ईरान
(b) जर्मनी
(c) सऊदी अरब
(d) दक्षिण अफ्रीका

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ईरान-अमेरिका संबंध बिगड़ने से चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश प्रभावित होगा।
2. वर्तमान में (2018) ईरान, भारत का तीसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. भारत ने एस-400 मिसाइल प्रणाली काटसा (सीएसटीएसए) के तहत खरीदी गयी है।
2. भारत ने एस-400 मिसाइल प्रणाली, काटसा (सीएएटीएसए) की परवाह न करते हुए रूस से खरीदा है।
3. ईरान के संबंध में भारत का मानना है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करेगा, एकतरफा प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अमेरिका-ईरान संबंध बिगड़ने से भारत पर इसका व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है यद्यपि भारत को अमेरिका की ओर से छूट मिली है किंतु वह खोखली अधिक प्रतीत होती है। विश्लेषण कीजिए। (शब्द-250)

नोट :
2 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) और 2(b) होगा।